भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2064
उत्तर देने की तारीख 11 फरवरी, 2026

5जी नेटवर्क कवरेज

2064. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उपभोक्ताओं की संख्या के मामले में भारत विश्व में 5जी सेवाओं का दूसरा सबसे बड़ा प्रयोक्ता बन गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत एक वर्ष के दौरान विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ग) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार 5जी नेटवर्क कवरेज का ब्यौरा क्या है;

(घ) 5जी को अपनाने से डिजिटल समावेशन, नवाचार, रोजगार सृजन और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, विनिर्माण और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ङ) 5जी पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार में साइबर सुरक्षा, डाटा गोपनीयता और नेटवर्क प्रतिरोध क्षमता से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, भारत में 385 मिलियन से अधिक 5जी वायरलेस डेटा उपभोक्ता और 10 मिलियन से अधिक एफडब्ल्यूए (फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस) उपभोक्ता हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5जी बाजार है।

(ख) भारत में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या मार्च 2024 में 1198.75 मिलियन से 0.24% बढ़कर मार्च 2025 में 1201.67 मिलियन हो गई। इस अवधि के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन 0.15% बढ़कर 533.34 मिलियन से 534.11 मिलियन हो गए।

(ग) 31-12-2025 की स्थिति के अनुसार, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने देश भर में 5.18 लाख बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) संस्थापित किए हैं। वर्तमान में, 5जी सेवाएं देश के 3.66 लाख से अधिक गांवों में उपलब्ध हैं। बीटीएस और 5जी सेवा युक्त गांवों की राज्यवार संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

(घ) 5जी, पूर्व 4जी मोबाइल प्रौद्योगिकी की तुलना में उच्च पीक डेटा दरों, कम विलंबता और उच्च स्पेक्ट्रम दक्षता के लाभ प्रदान करती है। 5जी के इन लाभों से डिजिटल समावेशन, नवाचार, रोजगार सृजन और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, विनिर्माण और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में व्यापक लाभ होने की उम्मीद है।

(ङ) सरकार ने संचार साथी, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म, एएसटीआर (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन)-एआई द्वारा धोखाधड़ी का पता लगाना, एफआरआई (वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम सकेंतक), इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ कॉल रोकने वाली प्रणाली और डिवाइस सेतु-इंडियन काउंटरफिटेड डिवाइस रिस्ट्रिक्शन सिस्टम जैसी पहलें की हैं ताकि दूरसंचार साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके, डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके और दूरसंचार जनित धोखाधड़ियों के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाई जा सके।

सरकार, भारत में दूरसंचार उपकरणों के सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क को चालू कर रही है। भारतीय दूरसंचार सुरक्षा आश्वासन आवश्यकताओं (आईटीएसएआर) को 5जी नेटवर्क के कार्यों सहित विभिन्न नेटवर्क कार्यों के लिए अधिसूचित किया जा रहा है।

डिजिटल निजी डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("डीपीडीपी अधिनियम") में उन्नत दूरसंचार और 5जी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संसाधित डेटा सहित डिजिटल निजी डेटा को संसाधित करने को नियंत्रित करने वाले एक वैधानिक फ्रेमवर्क की स्थापना की गई है। इस अधिनियम में प्राइवेसी-बाई -डिज़ाइन और सुक्योरटी-बाई-डिज़ाइन सिद्धांतों को लागू किया गया है जो दूरसंचार नेटवर्क, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कनेक्टेड 5जी सेवाओं द्वारा संचालित किए जाने वाले निजी डेटा की सुरक्षा के लिए सीधे प्रासंगिक हैं, जिससे डेटा संरक्षण, नेटवर्क अनुकूलन और साइबर सुरक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में सुदृढ़ हो जाता है।

सरकार ने आपातकालीन स्थितियों के दौरान नेटवर्क अनुकूलन और समन्वित राष्ट्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपायों को शामिल करते हुए एक एसओपी (मानक प्रचालन प्रक्रिया) भी निर्धारित की है।

अनुलग्नक-I

"5जी नेटवर्क कवरेज" के संबंध में 11 फरवरी 2026 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2064 के भाग (ग) के उत्तर के लिए संदर्भित अनुलग्नक

दिनांक 31.12.2025 तक 5जी बीटीएस और 5जी कवर किए गए गांवों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	5जी बीटीएस संख्या	5जी कवरेज वाले गांवों की संख्या*
आंध्र प्रदेश	20,650	8,530
अरुणाचल प्रदेश	704	562
असम	10,068	3,688
बिहार	27,535	42,836
छत्तीसगढ़	7,221	9,108
गोवा	1,077	314
गुजरात	35,413	15,707
हरियाणा	18,851	6,426
हिमाचल प्रदेश	4,582	11,171
झारखंड	10,519	19,241
कर्नाटक	34,392	19,657
केरल	21,813	1,334
मध्य प्रदेश	22,182	27,961
महाराष्ट्र	54,261	31,784
मणिपुर	1,349	647
मेघालय	892	1,119
मिजोरम	508	74
नागालैंड	820	245
ओडिशा	14,361	2,948
पंजाब	17,838	11,666
राजस्थान	31,034	20,634
सिक्किम	355	349
तमिलनाडु	37,735	9,377
तेलंगाना	19,563	1,945
त्रिपुरा	1,397	857
उत्तर प्रदेश	60,168	78,542

उत्तराखंड	6,053	4,729
पश्चिम बंगाल	33,791	31,004
अंडमान और निकोबार	138	35
चंडीगढ़	809	-
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	438	94
दिल्ली	13,558	55
जम्मू और कश्मीर	7,805	3,704
लद्दाख	302	22
लक्षद्वीप	4	3
पुडुचेरी	668	96
समस्त भारत	**5,18,854**	**3,66,464**

**आरजीआई के आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,44,131 है।*

****